

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 23/2018/अपील/आम्स/बूंदी

दायरा दिनांक 6.8.2018

किस्म अपील: धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

### अनवान

प्रभातीलाल पुत्र पोखरलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बूंदी-राज0।

....अपीलार्थी

### बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी।

....रेस्पोंडेन्ट



उपस्थित : श्री दिनेश सिंह अभिभाषक अपीलार्थी  
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोंड

### :: निर्णय ::

दिनांक 22.10.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या/144 दिनांक 23.5.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

- 1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1149/93 वैधता अवधि 31.12.2017 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने पत्रांक/DSB/Bundi/18/3589 दिनांक 7.4.2018 से अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध मुक0 नं0 20/2000 धारा 147,148,149,323,325,ता.हि. थाना रानोली जिला सीकर में दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2004 को दोषमुक्त किया जाना वर्णित करते हुये आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण व दस्तावेजात का अवलोकन कर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास शस्त्रअनुज्ञापत्र का धारित रहना लोकशांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कतई उचित प्रतीत नहीं से शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1149/93 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर धारित शस्त्र 12 डीबीबीएल गन नं0 8391 को जिला शस्त्रागार बूंदी में जमा कराने का जेरअपील आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील पेश कर निवेदन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट में प्रकरण में दोषमुक्त होने, चाल-चलन ठीक होने का उल्लेख करते हुये अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की गई जो कानूनी व तथ्यात्मक भूल है। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त आज तक अपीलांत के विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त प्रकरण अपीलांत के भाई जिला परिषद सीकर के सदस्य के चुनाव के दौरान रजिंशवश दर्ज करवाया गया था जिसमें अपीलांत दोषमुक्त हो चुका है। न्यायालय द्वारा दोषीकरार नहीं दिये

संभागीय आयुक्त  
कोटा सभाग, कोटा

जाने के उपरांत भी अपीलांट को आपराधिक प्रवृत्ति का मानने व लोकशांति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से लाईसेन्स निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। जेरअपील आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 4.6.2018 को जानकारी करने पर हुई जिसकी नकल 28.6.2018 को प्राप्त होने पर अपील पेश की गई अतः अपील पेश करने में हुई देरी क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश निरस्त किया जाकर अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई। xx

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई। xx
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं कर त्रुटि की है क्योंकि रिपोर्ट में आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त होना व अपीलार्थी का चाल चलन अच्छा होना वर्णित किया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हुये जेरअपील आदेश से शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निर्णय दिनांक 11.12.2004 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुये जाहिर किया कि अपीलांट उक्त प्रकरण में दोषमुक्त हुआ है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। लोकशांति व कानून व्यवस्था भंग करने संबंधी पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अन्त में विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये जेरअपील आदेश निरस्त करने एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।
- 4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध गम्भीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है जिससे अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृत्ति का होना प्रकट होता है तथा उक्त आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं किये जाने के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है अतः अपील खारिज की जावे। xx
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है अतः प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू पर विचार किया जाकर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी ने डिले कन्डोन हेतु प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण बीमार होने के कारण अपील समय पर पेश नहीं करना अंकित करते हुये इस आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसका रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने खण्डन नहीं किया ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र में

उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। लिहाजा न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

- 6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर अवलोकन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट में अनुज्ञापत्रधारी/अपीलार्थी मुक० नं० 20/2000 धारा 147,148,149,323,325,ता.हि.में दोषमुक्त किया जाना वर्णित किया है जिसकी पुष्टि प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि० सीकर (राज०) द्वारा आपराधिक प्रकरण सं० 66/2000 राज० राज्य बनाम सीताराम वगेश में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2004 की प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसी स्थिति में उक्त आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के आधार पर लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं किये जाने संबंधी जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अन्य ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृत्ति का होना प्रकट करते हो तथा लोकशांति व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अपीलांत द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में समुचित तथ्यों को परीक्षण किये बिना ही मात्र जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की आधारहीन रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय/आदेश को न्यायोचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संख्या/144 दिनांक 23.5.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजि० बूंदी को उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलार्थी के चाल चलन एवं आपराधिक प्रवृत्ति के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबंध में पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय/आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। xx
- 7 निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( के० सी० वर्मा )  
 सहायक आयुक्त  
 कोटा  
 कोटा सभाग, कोटा